in some criminal unlawful activities, definitely, he will be taken to task. But that does not mean that an important organisation like the Institute of Chartered Accountants should be blamed as an institution. Some individual members may be recalcitrant but a highly professional body should not be painted blackly.

बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियां

*66. **श्री शिवानन्द तिवारी:**††
श्री राम जेठमलानी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक बैंकों में वर्ष 2008-09 की दिसम्बर, 2008 को समाप्त हुई तिमाही में अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस-किस बैंक में अनर्जक परिसंपत्तियों से तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है; और

(ग) यह वृद्धि किन-किन उद्योगों में पाई गई है और उद्योग-वार इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 31 मार्च, 2008 की स्थिति की तुलना में 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, 76 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में से 38 बैंकों ने वृद्धि सूचित की है, 18 बैंकों ने लगभग कोई परिवर्तन नहीं होने की सूचना दी है तथा 20 बैंकों ने अपनी सकल अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी सूचित की है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि के बैंक-वार ब्यौरे विवरण में पर दिए गए हैं, (नीचे **देखिए**)। तथापि, सम्पूर्ण बैंकिग क्षेत्र की सकल अनर्जक परिसंपत्तियों के प्रतिशत में 31 मार्च, 2008 में 2.39% से 31 दिसम्बर, 2008 में 2.34% के रूप में कमी आई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली अनर्जक परिसंपत्तियों की उद्योग-वार सूचना प्रस्तुत नहीं करती है। तथापि, 31 मार्च, 2008 तथा 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक परिसंपत्तियां नीचे तालिका में दी गई हैं:-

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	क्षेत्र	मार्च, 2008	दिसम्बर, 2008
1.	कृषि	9,735	6,887
2.	लघु उद्योग	6,521	7,089
3.	अन्य	12,851	14,699
4.	कुल प्राथमिकता क्षेत्र (1+2+3)	29,107	28,675
5.	सरकारी क्षेत्र	299	249
6.	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	26,436	32,727
7.	सकल योग (4+5+6)	55,842 (2.39%)	61,651 (2.34%)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत हैं)

††सभा में यह प्रश्न श्री शिवानन्द तिवारी द्वारा पूछा गया।

विवरण-I

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि का विवरण
(31 *दिसम्बर*, 2008)

क्रम सं.	बैंक का नाम	सकल अनर्जक परिसंपत्तियां		
		मार्च, 2008	दिसम्बर, 2008	परिवर्तन % में
1	2	3	4	5
	सरकारी **क्षेत्र के बैंक**			
1.	इलाहाबाद बैंक	1,009	1,015	0.6
2.	बैंक ऑफ इंडिया	1,783	2,004	12.4
3.	केनरा बैंक	1,391	2,487	78.8
4.	देना बैंक	573	585	2.1
5.	आईडीबीआई बैंक लि.	1,377	1,454	5.6
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	916	1,486	62.2
7.	पंजाब एंड सिंध बैंक	136	152	11.8
8.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	761	976	28.3
9.	विजया बैंक	512	651	27.1
10.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	312	407	30.4
11.	भारतीय स्टेट बैंक	12,576	12,596	0.2
12.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	359	394	9.7
13.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	571	624	9.3
	गैर-सरकारी **क्षेत्र के नए बैंक**			
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	486	779	60.3
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	63	166	163.5
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	904	1,907	111.0
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	7,570	8,950	18.2
18.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	453	732	61.6
19.	यस बैंक लि.	11	48	336.4
	गैर-सरकारी **क्षेत्र के पुराने बैंक**			
20.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	126	150	19.0
21.	कैथोलिक सिरीयन बैंक लि.	131	166	26.7
22.	सिटी यूनियन बैंक लि.	83	111	33.7
23.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	63	66	4.8

1	2	3	4	5
24.	फेडरल बैंक लि.	469	626	33.5
25.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	116	194	67.2
26.	कर्नाटक बैंक लि.	380	451	18.7
27.	करूर वैश्य बैंक लि.	194	226	16.5
28.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	138	147	6.5
29.	नैनीताल बैंक लि.	19	21	10.5
30.	साउथ इंडियन बैंक लि.	188	208	10.6
	विदशी **बैंक**			
31.	एबीएन आमरो बैंक एन.वी.	294	472	60.5
32.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	58	63	8.6
33.	बारक्लेज बैंक पीएलसी	61	688	1027.9
34.	सिटीबैंक एन.ए.	1,011	1,323	30.9
35.	ड्यूश बैंक (एशिया)	60	196	226.7
36.	डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि.	5	24	380.0
37.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	697	1,017	45.9
38.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	723	882	22.0

Non-performing assets with banks

†*66. SHRI SHIVANAND TIWARI:††
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in many banks of the country, non-performing assets are piling up in the quarter ending December, 2008 pertaining to the year 2008-09;

(b) if so, the names of the banks where non-performing assets have comparatively increased during the aforesaid period; and

(c) the names of industries in which this increase has been noticed and the percentage of increase, industry-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As on 31st December, 2008 out of total 76 scheduled commercial banks (SCBs), 38 banks have reported increase, 18 banks have reported almost no change and

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shivanand Tiwari.

20 banks have reported decline in their absolute gross non-performing assets (NPAs), as compared to the position as on 31st March, 2008. The bank-wise details of increase in gross NPAs of SCBs are given in the Statement-I (*See* below). However, for the entire banking sector, the gross NPA percentage declined from 2.39% as on 31st March, 2008 to 2.34% as on 31st December, 2008.

(c) The existing Management Information System of Reserve Bank of India does not generate industry-wise information of NPAs. However, the gross NPAs of SCBs in the Priority and Non-priority sectors, as on 31st March 2008 and 31st December, 2008 are given in the table below:

(Amount Rs. in crore)

Sl.No.	Sector	March, 2008	December, 2008
1.	Agriculture	9,735	6,887
2.	Small Scale Industries	6,521	7,089
3.	Others	12,851	14,699
4.	Total Priority Sector (1+2+3)	29,107	28,675
5.	Public Sector	299	249
6.	Non-priority Sector	26,436	32,727
7.	Gross Total (4+5+6)	55,842 (2.39%)	61,651 (2.34%)

(Figures in brackets are percentage of gross NPAs to gross advances)

Statement-I

Statement of increase in Gross NPAs of Scheduled Commercial Banks
(31st *December*, 2008)

Sl. No.	Bank Name	Gross NPAs		
		March 2008	December 2008	Change in %
1	2	3	4	5
	Public Sector Banks			
1.	Allahabad Bank	1,009	1,015	0.6
2.	Bank of India	1,783	2,004	12.4
3.	Canara Bank	1,391	2,487	78.8
4.	Dena Bank	573	585	2.1
5.	IDBI Bank Limited	1,377	1,454	5.6

1	2	3	4	5
6.	Indian Overseas Bank	916	1,486	62.2
7.	Punjab & Sind Bank	136	152	11.8
8.	United Bank of India	761	976	28.3
9.	Vijaya Bank	512	651	27.1
10.	State Bank of Hyderabad	312	407	30.4
11.	State Bank of India	12,576	12,596	0.2
12.	State Bank of Mysore	359	394	9.7
13.	State Bank of Travancore	571	624	9.3
	New Private Banks			
14.	Axis Bank Ltd.	486	779	60.3
15.	Development Credit Bank Ltd.	63	166	163.5
16.	HDFC Bank Ltd.	904	1,907	111.0
17.	ICICI Bank Ltd.	7,570	8,950	18.2
18.	Kotak Mahindra Bank Ltd.	453	732	61.6
19.	Yes Bank Ltd.	11	48	336.4
	Old Private Banks			
20.	Bank of Rajasthan Ltd.	126	150	19.0
21.	Catholic Syrian Bank Ltd.	131	166	26.7
22.	City Union Bank Ltd.	83	111	33.7
23.	Dhanalakshmi Bank Ltd.	63	66	4.8
24.	Federal Bank Ltd.	469	626	33.5
25.	ING Vysya Bank Ltd.	116	194	67.2
26.	Karnataka Bank Ltd.	380	451	18.7
27.	Karur Vysya Bank Ltd.	194	226	16.5
28.	Lakshmi Vilas Bank Ltd.	138	147	6.5
29.	Nainital Bank Ltd.	19	21	10.5
30.	South Indian Bank Ltd.	188	208	10.6
	Foreign Banks			
31.	ABN AMRO Bank N.V.	294	472	60.5
32.	Bank of Bahrain and Kuwait BSC	58	63	8.6
33.	Barclays Bank Plc	61	688	1027.9

1	2	3	4	5
34.	Citibank N.A.	1,011	1,323	30.9
35.	Deutsche Bank (Asia)	60	196	226.7
36.	Development Bank of Singapore Ltd.	5	24	380.0
37.	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	697	1,017	45.9
38.	Standard Chartered Bank	723	882	22.0

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने टेबल के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि किस सेक्टर में एन0पी0ए0 की क्या स्थिति है। उसमें एक आश्चर्यजनक बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्च, 2008 और दिसम्बर, 2008 में 2848 करोड़ रुपए की कमी आई है, लेकिन अदर्स सेक्टर में 1848 करोड़ रुपए और नॉन प्रॉयरिटी सेक्टर में 6291 करोड़ रुपए की एन0पी0ए0 में वृद्धि हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अदर्स और नॉन प्रॉयरिटी सेक्टर में काफी वृद्धि हुई है, इसका क्या कारण है और इसके निदान का क्या उपाय सरकार कर रही है?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं जो फार्म लोन वेवर स्कीम सरकार की बनी थी, उसके तहत किसानों को बहुत फायदा हुआ है। पहले जो बैंकों के रिकॉर्ड्स में एन0पी0ए0 चल रहे थे, उनको बहुत जगह से "राइट ऑफ" किया गया है। उसके कारण बहुत बड़ा अंतर आया है और उसके बाद बैंकों के एन0पी0ए0 वह नहीं रहे और आगे उनको लोन मिल पाए हैं। इस कारण से वह reflection अलग-अलग इस हिसाब से करेगा। हम उसका पूरे का पूरा ब्योरा दे सकते हैं कि किस किस बैंक में कितना कितना हुआ है।

श्री शिवानन्द तिवारी : सभापति महोदय, मैंने अदर्स और इसके बारे में कहा था। अभी मंत्री जी ने बताया है कि किसानों के लिए जो योजना तैयार की गयी, उसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में एन0पी0ए0 में कमी आयी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो किसानों के कर्ज की माफी हुई है, वह किसानों के लिए हुई है या बैंकों के लिए हुई है क्योंकि हमारा यह ख्याल है कि यह जो किसानों के कर्ज की माफी हई है, उससे किसानों को राहत नहीं मिली है, बैंकों को राहत मिली है। उनका नॉन प्रॉफिटेबल असेट रिकवर हो गया है। महोदय, मंत्री जी के बयान से तो यही लग रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि इन्होंने वाकयी बैंकों को राहत दी है या किसानों को राहत दी है? दूसरे जिन दो सेक्टर्स - नॉन प्रॉयरिटी सेक्टर में 6291 करोड़ रुपए की और अदर्स में 1848 करोड़ रुपए की एक साल में वृद्धि हुई है, उसका क्या कारण है?

श्री पवन कुमार बंसल: सर, मुझे यह नहीं मालूम कि माननीय सदस्य ने यह अनुमान कैसे लगाया कि जो loan waiver हुआ, उसका फायदा किसानों को नहीं बल्कि बैंकों को मिला। सर, सभी यह जानते हैं कि इतना पैसा जो किसानों के जिम्मे पड़ा था, जब उसको माफ किया गया तो उसका सबसे बड़ा फायदा सीधे उन्हीं किसानों को हुआ क्योंकि अब उन्हीं को नया लोन मिलना शुरू हुआ जो कि पहले नहीं मिल रहा था। देश में 80 फीसदी से ज्यादा गरीब, छोटे और लघु किसान हैं जिनको उसके कारण सभी जगह फायदा मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर इसको पूरे तौर पर मॉनिटरिंग कर रहा है कि उनको नया लोन मिल पाये ताकि उसके बाद वे उस पैसे से अपना उत्पादन बढ़ा सकें और इस तरह देश में अन्न का जो उत्पादन है, वह भी बढ़ सके। सर, इसका फायदा सीधे-सीधे उनको मिला है। इसके पहले उसके नाम वे NPAs पड़े थे, जिनके कारण अगर वह लोन लेना चाहता तो इनवेस्टमेंट लोन वगैरह के लिए अगर उसके खिलाफ किसी भी ढंग से जहाँ कहीं भी collateral होती, उसका इस्तेमाल बैंक्स कर सकते थे।

सर, उन्होंने दूसरा सवाल यह पूछा है कि दूसरों का लोन कितना NPA हुआ है? यह सवाल पिछले नौ महीनों का है। इसके बावजूद, पिछले नौ महीनों में पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें जो advances थे, वे 17,97,504 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,14,117 करोड़ रुपये हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर हम पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर का हिसाब लगायें तो NPAs दर कम हुई हैं। किसी-किसी सेक्टर में यह जरूर बढ़ी हैं। आप जानते हैं कि सवाल का जोर भी इसी चीज पर है कि इन नौ महीनों में मंदी का जो दौर चला, जिसमें बहुत से लघु उद्योग, कारखाने और बहुत से लोगों ने जो पर्सनल लोन ले रखा था, जो priority sectors में as such नहीं आते थे, उनसे कहीं न कहीं चूक हो गई है। बैंकों ने जो एक तरीका अपनाया हुआ है, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू मानवता के आधार पर है कि किसी को दिक्कत या मुश्किल न आये, इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो उनके लोन period को लम्बा कर दिया जाए ताकि उस समय में वे आसानी से लोन लौटा सकें। दूसरी तरफ, बैंकों ने लगातार यह प्रयास रखा है कि उनका ऋण जो अतिदेय हो गया है, वह बैंक उसको वापिस कर सकें। इस प्रकार, पूरी की पूरी जो तस्वीर है, वह बिल्कुल साफ है। NPAs की दर पहले के औसत के हिसाब से बहुत कम हुई हैं और यह record है कि net NPAs एक परसेंट पर पहुँच गई हैं।

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, I have seen the reply given by the hon. Minister. Yes, there is some change so far as the NPAs are concerned. Percentage-wise, it is very little, and there is no effect of it. It is only .05 per cent.

So, part (a) of my question is, what action the Government has taken to reduce these types of NPAs substantively? Then, part (b) of my question is this. Sir, I have seen the list provided here. There are public sector banks, new private banks, old private banks and foreign banks. The question was regarding banks, but there is no mention of the cooperative banks of the country. Sir, we all know that these cooperative banks play a great role in providing institutional credit to agriculture, small industries and to other different sections of the society. So, in this part of my question, may I know from the hon. Minister what is the position of cooperative banks so far as the NPAs are concerned?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, regarding the first part, I will first like to take only half-a-minute to inform the hon. Member and the House that over this period, from the period end-March, 1997, when the NPAs were as high as 15.7 per cent, because of the consistent efforts of the Government, a multi-pronged approach of the Government, these NPAs have come down to 2.3 per cent and the net NPAs, as I was referring, Sir, have come down — for the public sector banks — from 17.8 per-cent to 2.2 per cent and the net NPAs from 9.2 per cent to 1.0 per cent respectively. This is the record as far as the reduction in the NPAs is concerned. Sir, coming to the second part of the hon. Member's question, we, in the Government of India, directly have data which the Reserve Bank has, which is about the scheduled commercial banks, the public sector banks, the private sector banks and the foreign banks, which number 76 in all. Sir, the hon. Member has sought to seek information regarding the cooperative banks. I am afraid, we would not have that data readily available. But we can make an endeavour. It would be a very gigantic task to collect the data on NPAs of all cooperative banks from all over the country and it may well nigh be impossible for the Government of India to collect it. But, Sir, I

would like to take this opportunity to apprise the hon. Member of one fact that the Government of India is concerned about reviving and strengthening the cooperative credit structure in the country. For that, both short-term and long-term revived recapitalisation of the banks is under process. A good number of states have entered into Memoranda of Understanding with the Government of India as far as the recapitalisation and revival of short-term cooperative agricultural credit is concerned, and we are moving ahead in that direction. It is our endeavour to see, at the same time, that the cooperative banks, which are the backbone of the rural economy, also work, as vibrant and thriving institutions.

श्री प्रकाश जावेडकर : सभापति महोदय, मेरा एक pointed question है कि हम बैंकों के NPA और बैंकों की सम्पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं और शिवानन्द जी ने पूछा कि 65,000 करोड़ के जो कृषि कर्ज माफ हुए हैं, उनमें से बैंकों को सरकार ने कितने रुपए दिए? क्योंकि, सर, यह घोषणा तो हुई है, लेकिन बैंकों में पैसा जमा नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 65,000 करोड़ में से बैंकों को कितना रुपया किसानों की कर्ज माफी के लिए दिया गया है?

श्री पवन कुमार बंसल : सर, हम जब Supplementary Demands के लिए आए थे, उस वक्त उसका एक schedule दिया था कि कितना पैसा माफ हो रहा है, 15,000 और 10,000 करोड़ पहले है और बाकी दूसरे वर्ष में है।

श्री प्रकाश जावेडकर : नहीं सर, वही ..(व्यवधान)..

श्री सभापति : आप जरा सुन लीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : सर, कृपया मुझे सवाल का जवाब देने दें। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि उसका एक तरीका, जो रास्ता है, उसका जो प्रोसिज़र ..(व्यवधान)..

श्री प्रकाश जावेडकर : यानी बोझ आने वाली सरकार पर और क्रेडिट आपको!

श्री सभापति : आप जरा उत्तर सुन लीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : सर, जो प्रोसिज़र, जो रास्ता उसके लिए तय हुआ है, वह यह है कि सभी बैंकों ने, एक-एक ब्रांच के हिसाब से, हालांकि आज का सवाल डायरेक्ट इससे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि मैं इसका जवाब दूं, सभी जगह एक-एक, पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर कि कितना, उस तारीख तक कितना ..(व्यवधान)..

श्री प्रकाश जावेडकर : आपने कितना दिया?

श्री सभापति : आप सवाल का जवाब सुन लीजिए, प्लीज़।

श्री पवन कुमार बंसल : सर, अभी तक 15,000 और 10,000 यानी 25,000 करोड़। ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN : This interruption is not going to help at all.

श्री पवन कुमार बंसल : सर, वह schedule बना हुआ है; This does not really arise out of this question. लेकिन उसका पूरा ब्यौरा, जितना-जितना जिस-जिस तारीख को हम दे चुके हैं और आगे क्या होना है, वह मैं माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा। लेकिन, यह सवाल, NPA से ताल्लुक रखता है, it does not really arise out of this question.